मध्यप्रदेश का वार्षिक बजट आज

संभावित प्रावधान

27 हजार करोड़ किसानों की बिजली के लिए

20 हजार करोड़ फसल सिंचाई के लिए

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पेश करेंगे वित्त वर्ष 2026-27 का बजट | 4 लाख 80 हजार करोड़ के आंकड़े को छू सकता है बजट

कन्हैया लोधी

भोपाल, 17 फरवरी. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश करेंगे. बजट पेश करने के लिए वित्त विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी.

इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट के सामने बजट को लेकर प्रेजेंटेशन हो चुका है, उसके बाद बजट में मामूली बदलाव किए गए हैं. मिले संकेतों के मुताबिक नए वित्त वर्ष का बजट अब पहली बार पांच लाख करोड़ के दहलीज पर पहुंचने के करीब है. इस बार का बजट कम से कम 4 लाख 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है. वित्त विभाग ने जो कवायद की है, उस हिसाब से बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है. ये बजट सरकार की प्राथमिकता में शामिल चार मिशनों पर एक बार फिर केंद्रित रहेगा. इसमें गरीब, युवा, किसान और महिला शामिल है. इस बार के बजट में किसानों की बिजली के लिए 27 हजार करोड़ रुपए तो सिंचाई के लिए कम से कम 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है. इधर पिछले विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए भी सरकार लगभग 23 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम कर सकती है. लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए भी 12 सौ करोड़रुपए से अधिक का प्रावधान किया जा सकता है. इस तरह किसान और महिला के लिए ही 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का इंतजाम बजट में किया जा सकता है.

बजट में प्रदेश के युवाओं को भी बजट में सरकार निराश नहीं करेगी. नए वित्तीय वर्ष में उन्हें 50 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नौकरी का भरोसा मिल सकता है. वैसे भी सरकार ने मौजूदा कार्यकाल तक दो लाख सरकारी पदों पर भर्ती का वादा किया है. लिहाजा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को तेजी से भर्ती प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि ये केवल चुनावी बनकर नहीं रह जाए.

पूंजीगत खर्च को बढ़ाएगी सरकार

राज्य सरकार इस बार पूंजीगत खर्च को बढ़ा सकती है और ये आंकड़ा अब एक लाख 10 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है. इससे निर्माण कार्य से जुड़े विभागों को स्थायी श्रेणी के निर्माण के लिए ज्यादा राशि मिल सकेगी. पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहिन राशि मिल सकती है. ये स्कीम पिछले चार वर्ष से चल रही है, जिसका फायदा उठाने में मप्र देश के अग्रणी राज्यों में बना हुआ है. वहीं राजकोषीय घाटा को 4.66 फीसदी से कम करने की तैयारी की गई है और इसे 4.50 तक सीमित किया जा सकता है. इससे सरकार का वित्तीय प्रबंधन बेहतर हो सकेगा. वहीं इस बार राज्य सरकार के वेतन-भत्ते पर खर्च की राशि बढ़कर 90 हजार करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकती है.

जीएसडीपी के अनुमानों को झटका

पिछले वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-26 की अवधि में जीएसडीपी 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया था, लेकिन मंगलवार को जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, उसमें अनुमानों को संशोधित कर 16 लाख 69 हजार 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इस तरह इसमें 24727 करोड़ रुपए की कमी की गई है, जो कि राज्य के लिए किसी झटके से कम नहीं है. इसलिए नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जीएसडीपी के अनुमान को लगभग 18 लाख 20 हजार करोड़ रुपए के आसपास सीमित रख सकती है.

मिड डे मिल में बच्चों को मिल सकता है ट्रेटा पैक दूध

बजट में प्रदेश के एक करोड़ 40 लाख से अधिक नौनिहालों को अब ट्रेटा पैक में दूध देने की योजना तैयार की गई है, जिसकी घोषणा हो सकती है. इधर सीएम केयर का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी की गई है, जिसके तहत हार्ट और कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज अब मेडिकल कॉलेजों में देने की व्यवस्था की जा सकती है. किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट को भी बढ़ाया जा सकता है. हर जिले में यूनिट की स्थापना की घोषणा हो सकती है. एमबीबीएस की सीटों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे लेकर बजट में घोषणा हो सकती है. बजट में दो सौ नए सांदीपनि विद्यालय खोलने की घोषणा की जा सकती है. हाल ही में इस संबंध में कैबिनेट ने भी निर्णय लिया है.

विधानसभा में अध्यक्ष तोमर से सीएम यादव ने की भेंट

भोपाल. विधानसभा में अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भेंट की. विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हुआ है और बुधवार को सदन में राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश होगा.

वित्तीय स्थिति पर पटवारी चिंतित

- केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कम होने का मुद्दा उठाया

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 फरवरी. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने और मुलाकात का समय मांगा है.

पटवारी ने पत्र में लिखा है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 7.85 प्रतिशत से घटाकर 7.35 प्रतिशत कर दी गई है. इससे वर्ष 2026 से 2031 के बीच प्रदेश को लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह कटौती विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकती है, खासकर तब जब राज्य पर कुल सार्वजनिक ऋण 5.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो वार्षिक बजट से भी अधिक है.

चालू वित्तीय वर्ष में उधारी 72,900 करोड़ रुपये तक पहुंचने और बड़ी राशि के अव्ययित रहने पर उन्होंने वित्तीय अनुशासन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य के आगामी बजट के मद्देनजर केंद्र सरकार से कर-वितरण व्यवस्था की समीक्षा और वित्तीय निगरानी मजबूत करने की आवश्यकता है.

23 प्रतिष्ठानों पर 54 लाख का जुर्माना

मुरैना, 17 फरवरी. मुरैना के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत ने मिलावट पाए जाने पर 23 प्रतिष्ठानों पर कुल 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. समय पर जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी दिए गए हैं. दीपावली के दौरान शिकायतें मिली थीं कि खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले कुछ प्रतिष्ठान बड़े पैमाने पर मिलावट कर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं. शिकायतों के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग नें डेयरी, मावा और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई और वे प्रयोगशाला भेजे गए थे.

तृतीय अनुपूरक बजट पेश

19,287 करोड़ रुपयों का प्रावधान

भोपाल, 17 फरवरी. मध्यप्रदेश विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें 19287.32 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है.

मौजूदा वित्त वर्ष के इस अंतिम अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 4700 करोड़ रुपयों का प्रावधान नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए किया गया है. इसके साथ ही 1810 करोड़ रुपयों की राशि का प्रावधान राज्य सरकार पर विभिन्न प्रकार के ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए किया गया है.

बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को पेश किए गए तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 23 फरवरी का दिन निर्धारित किया है. चर्चा के बाद इसे सदन में पारित किया जाएगा.

तृतीय अनुपूरक बजट की कुल 19,287.32 करोड़ रुपए की राशि में से राजस्व मद में 8,934.03 करोड़ तथा पूंजीगत मद में 10,353.29 करोड़ का प्रावधान है. मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विवेकाधीन अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के लिए 1703 करोड़, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के लिए 1250 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 2630 करोड़ रुपयों की राशि प्रावधानित की गयी है.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए 18,67 करोड़ प्रस्तावित हैं. इस बजट में अन्य विभागों के लिए अनुपूरक बजट के प्रस्ताव समाहित किए गए हैं.

प्रहलाद पटेल ने सदन में दी चुनौती

भोपाल. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य में अगर किसी के पास जॉब कार्ड होने के बाद उसे काम नहीं मिलने की बात सामने आई तो वे सदन में माफी मांग लेंगे. प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने श्योपुर जिले से सहरिया आदिवासियों के पलायन की बात कहते हुए सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में गांव के गांव खाली हो गए हैं और जनता रोजगार की तलाश में राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे स्थानों पर पलायन कर रही है. कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय ने उनका समर्थन किया. इस पर पटेल ने चुनौती दी.

पेज तीन का शेष

जीएसडीपी में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि

सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत फसलों का सर्वाधिक योगदान 30.17 प्रतिशत रहा. इसके बाद पशुधन 7.22 प्रतिशत, वानिकी 2.13 प्रतिशत, मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि 0.61 प्रतिशत तथा खनन एवं उत्खनन 2.96 प्रतिशत रहा. प्राथमिक क्षेत्र का कुल मूल्य 6,33,532 करोड़ से बढ़कर 6,79,817 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे 7.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. द्वितीयक क्षेत्र का जीएसवीए 2,84,125 करोड़ से बढ़कर 3,12,350 करोड़ हो गया है और यह वृद्धि 9.93 प्रतिशत है. तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक 15.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और इसका कुल मूल्य 5,85,588 करोड़ है. इसके अलावा राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,618 करोड़ के राजस्व आधिक्य का अनुमान है तथा राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.66 प्रतिशत रहने का अनुमान है. कर राजस्व में 13.57 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है. वर्ष 2024-25 में कुल फसल उत्पादन में 7.66 प्रतिशत तथा खाद्यान्न उत्पादन में 14.68 प्रतिशत की वृद्धि सामने आई है. राज्य में दुग्ध उत्पादन 225.95 लाख टन तक पहुँच गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. औद्योगिक विकास के अंतर्गत 1,028 इकाइयों को 6,125 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिनसे 1.17 लाख करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 1.7 लाख रोजगार सृजन की संभावना है. राज्य में 1,723 स्टार्टअप और 103 इनक्यूबेशन केंद्र संचालित हैं, जो नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं. इसी तरह अमृत 2.0 के अंतर्गत 24,065 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14